

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)

O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX;

केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, सातवीं मंजिल, पोलिटेकनिक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद 380015 7th Floor, Central Excise Building,
Near Polytechnic,

Ambavadi, Ahmedabad-380015

2: 079-26305065

टेलेफेक्सं: 079 - 26305136

रजिस्टर डाक ए .डी .द्वारा

क फाइल संख्या (File No.) : V2(94)91 /Ahd-II/Appeals-II/ 2016-17 स्थगन आवेदन संख्या(Stay App. No.):

ग ______ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-IV), अहमदाबाद- ॥, आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश सं _____ दिनांक _____ से सृजित Arising out of Order-In-Original No . 898/Refund/2010 _ Dated: 17/05/10 issued by: Assistant Commissioner Central Expise (Div-IV), Ahmedabad-II

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Jason Décor Pvt. Ltd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पूनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है |

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India:

(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राज्स्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए |

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो |

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित हैं |



(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केंडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपन्न संख्या इए—8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल—आदेश एवं अपील आदेश की दो—दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके जाथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35—इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर—6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/— फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/— की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:Under Section 35B/35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं
- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.
- (ख) उक्तिलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ—20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद—380016.
- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad: 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.
- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धार 6 के अंतर्गत प्रपन्न इ.ए—3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तिर्धि रूपए 5000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/— फीस भेजनो होगी। की फीस सहायक रिजस्टार के नाम

रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक अवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवांकर अपीलीय न्यायाधिकरण किया विधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवांकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपीलों के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (j) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है .

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal perfore CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में ,इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

ORDER-IN-APPEAL

M/s Jason Décor Pvt Ltd, Opp Moraiya Bus Stand, Village-Chachrawadi Vasana, Taluka-Sanand, Dist-Ahmedabad, Gujarat (hereinafter referred to as "the Appellant"), has filed the present appeal against the Order-in-Original No. 898/Refund/2010 dated 17.05.2010(hereinafter referred to as 'impugned orders') passed by the Assistant Commissioner of Central Excise, Division-IV, Ahmedabad-II, Ahmedabad (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- The facts of the case, in brief, the appellant are register with the Central 2. Excise Department having registration no. AABCJ 2874R XM001 and engaged in manufacturing of Laminated Bagasse Board & Laminated Medium Density Fiber Board falling under chapter 44 of Central Excise Traiff Act, 1985. It is observed that the appellant has filed a refund claim of Rs 5,22886/- on the ground that they have debited the said amount as per the direction given by the Audit Party. However they come to know that they have wrongly paid the duty alongwith interest. Hence they filed the refund. The Audit party observed that Appellant has manufactured intermediate product namely Resin Falling under chapter 39 of CETA 1985. The said product is used as binder in the manufacturing of Bagasse Board. Resin is captively used in the manufacture of final product which is cleared at Nil rate of Duty. The appellant has purchased exempted Bagasse Board. The design paper is laminated /pasted on Bagasse Board with the help of Resin. The Resin is manufactured in house only and not sold in the market as it is used capt vely. The Audit is in a view that they cannot take the benefit of Notification No 67/95 dated 16.03.1995 on Resin is used captively as the finished product is chargeable Nil Rate of duty. Accordingly department issued the SCN to the appellant which was adjudicate by the impugned orders. The refund claim filed by the Appellant is rejected.
- 3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant has filed the present appeal on the ground that they have not availed any benefit of Notification No 67/95 dated 16.03.1995. Further Resin has not having any shelf life. Hence it is not marketable. They have relied upon the judgment viz M/s Moti Laminates Pvt Ltd Vs Collector of Central Excise reported in 1996-5(76) ELT 337 (SC). They have also relied upon the Board Circular No 464/30/99-Cx dated 30.06.1999.
- 4. Personal hearing in the case was granted on 22.03.2017 which was attended by Appellant representative. Written submission was also submitted at the time of personal hearing.
- I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of the appeal, put forth by the appellant. Looking to the facts of the case, I proceed to decide the case on merits.



- on the ground that they have not availed any benefit of Notification No 67/95 dated 16.03.1 995. Further Resin has not having any shelf life. Hence it is not marketable. They have relied upon the judgment Viz M/s Moti Laminates Pvt Ltd Vs Collector of Central Excise reported in 1996-5(76) ELT 337 (SC). They have also relied upon the Board Circular No 464/30/99-Cx dated 30.06.1999. The adjudicating authority was of the view that Resin is a well know product in the market and its marketability is not disputed. Further appellant has breached the condition of Notification No. 6/2006-CE (NT) as their final product is either chargeable to NIL rate of duty or it is exempted. The case relied by the appellant is not applicable to this case as Resin has shelf life and a well know product in the market.
- 7. Now issue to be decided is whether Resin manufactured and used captively is excisable or otherwise. Before going to the merits of the case, the brief history of the case is Appellant has filed a appeal before Commissioner (A) and the same was rejected. The Appellant further filed the appeal before the Hon'ble CESTAT who vide order no A/11217/2016 dated 19.10.2016 remanded the matter to Commissioner (Appeal). The Tribunal directed that in the earlier tribunal order no A/1927/WZB/AHD/2010 dated 14.12.2010, in the similar issue, the appeal filed by the same appellant. The case was remanded back to the appellate authority with a direction for fresh order in light of the order of the Supreme Court of India and the Board circular. On the basis of that, the matter was re-adjudicated by my predecessor. The appellate authority followed the direction given by the apex court that any goods attract excise duty must satisfy the test of marketability and Resin/Rasol is not excisable. Further Appellate authority found that Resin has limited shelf life, produced during the course of manufacturing and solely used capitively by the Appellant. Therefore same is not marketable and cannot be consider excisable. Since the issue is already settled as per the direction given by Tribunal in light of the order of Supreme Court of India, supra and the Board circular dated 30.06.1999, I follow the same. Therefore the OIO passed by the adjudicating authority is rejected. The appeal stands disposed of in above terms.
- 8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपीलों का निपटारा उपरोक्त तरीकें से किया जाता है।
- 8. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स **- II**)

CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

ATTESTED

SUPERINTENDENT (APPEAL), CENTRAL TAX, AHMEDABAD.

THE STORY OF THE PARTY OF THE P

To, M/s Jason Décor Pvt Ltd, Opp Moraiya Bus Stand, Village-Chachrawadi Vasana, Taluka-Sanand, Dist-Ahmedabad,

Copy To:-

- 1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad zone, Ahmedabad.
- 2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-II. Ahmedabad.
- 3. The Dy. /Assistant Commissioner, Central Excise Division-IV, Ahmedabad-II, Ahmedabad.
- 4. The Assistant Commissioner(Systems), Central Excise, Ahmedabad-II, Ahmedabad
- 5. Guard File.6. P.A. File.

